

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,

सचिव एवं विधि परामर्शी,

उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,

मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,

नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 16 मार्च, 2009

विषय: रोशनाबाद, जिला हरिद्वार स्थित जिला न्यायाधीश के आवास एवं न्यायिक अधिकारियों के टाईप-IV के 10 आवासों को रंगाई-पुताई आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-325/UHC/Admin.B/IX-b/2009, दिनांक 10.2.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रोशनाबाद, जिला हरिद्वार स्थित जिला न्यायाधीश के आवास एवं न्यायिक अधिकारियों के टाईप-IV के 10 आवासों को रंगाई-पुताई आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु प्रेषित रु० 13.01 (6.85 + 6.16) लाख के आगणन के सापेक्ष टैं०ए०सैं० द्वारा अनुमोदित धनराशि रु० 12,64,000/- (6.81 + 5.83) (बारह लाख चौसठ हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु० 12,64,000/- (बारह लाख चौसठ हजार रुपये मात्र) को धनराशि उपशीर्षक-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश के अन्तर्गत मद संख्या-29-अनुरक्षण में निवर्तन पर रखी गई धनराशि से व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेंट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, को स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- (4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- (5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (6) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टिसरमेंट) नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिश्रासों अधियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।

- (7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
 - (8) कार्य करते समय यह सुनिश्चित करते कि वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित नियमों एवं नार्मस से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न की जाय। इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा।
 - (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
 - (10) कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भूली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
 - (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2009 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
 - (12) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 की आय-प्रयक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजन-105-रिजल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-763NP/XXVII(5)/08, दिनांक 12.3.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(अरुंडी पालीवाल)

सचिव।

संख्या-61-धा(8)/XXXXVI(2)/2008-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओवरग्रेड बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, मानरा, देहरादून।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।
- 4- वरिष्ठ कौषाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार।
- 5- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
- 7- नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गाईड फाईल।

आज्ञा से

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव।